# चीनी मिलों की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए मीटिंग कल

[पीटीआई| नई दिल्ली]

**शुगर इंडस्ट्री** की मुश्किलों के मसले पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार की अगुवाई में मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की बैठक 18 दिसंबर को होगी। इसमें नकदी संकट से जूझ रही शुगर इंडस्ट्री को आगे और सहायता देने पर विचार किया जाएगा। इन उपायों में इंपोर्टेड चीनी के री-एक्सपोर्ट के लिए समयसीमा घटाने जैसे कदम भी शामिल हैं।

इससे पहले 6 दिसंबर को हुई पिछली बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से बनाई गई कमेटी ने शुगर इंडस्ट्री के लिए कई तरह के इनसेंटिव की सिफारिश की थी। इसके तहत गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 7,200 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन, रिजर्व बैंक के नॉर्म्स के मुताबिक लोन की रीस्ट्रक्चरिंग, 40 लाख टन कच्ची चीनी के प्रॉडक्शन के लिए सहायता और पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा 10 फीसदी तक बढ़ाने के अलावा बफर स्टॉक बनाए जाने जैसे उपायों की सिफारिश की गई थी।

फूड मिनिस्टर के वी थॉमस ने बताया, 'हम बुधवार को मिल रहे हैं जिसमें शुगर इंडस्ट्री को समस्याओं से निजात दिलाने के पैकेज के बारे में विचार किया जाएगा। मंत्रियों का एक अनौपचारिक समूह शुगर मिलों को राहत उपायों के बारे में विचार-विमर्श करेगा।' थॉमस ने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) की बाधाओं के कारण सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, 'हमारे पास एक रास्ता यह भी है कि एडवांस लाइसेंसिंग योजना के तहत इंपोर्टेड शुगर के फिर से एक्सपोर्ट के लिए समयसीमा को कम किया जाए। शुगर इंडस्ट्री की मांग है कि इंपोर्टेड चीनी के फिर से एक्सपोर्ट की समयसीमा को कम करके 3 महीने की जाए। क्या तीन महीने पर्याप्त होंगे? हमें विस्तार में चर्चा करनी होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि चीनी रिफाइनरियां देश में टिकाऊ बनें।'

**बैठक में** नकदी संकट से जूझ रही शुगर इंडस्ट्री को आगे और सहायता देने पर विचार किया जाएगा

थॉमस ने कहा कि सरकार चीनी मिलों को समर्थन देने के लिए सभी विकल्पों पर काम कर रही है, ताकि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा, 'इस बैठक के बाद हम मंत्रिमंडलीय सर्कुलर को अंतिम रूप देंगे।' प्रॉडक्शन कॉस्ट बढ़ने और पिछले कुछ साल में सरप्लस प्रॉडक्शन के कारण शुगर की कीमत कम हो गई है, जिससे चीनी उद्योग को फाइनेंशियल मोर्चे पर मुश्किल का सामना कर रहा है। शुगर इंडस्ट्री को नुकसान होने की वजह से पिछले साल का गन्ना बकाया लगभग 3,400 करोड़ रुपये का है। देश में चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु अहम हैं।

The Economic Times.
17-12-13